

प्रेषक,

आर०पी० फुलोरिया  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग

देहरादून

दिनांक 17 मार्च 2008

विषय:- अनुदान संख्या-19, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास  
कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-07-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) में पुनर्विनियोग के  
संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 968/रा.नि.आ./2007 दिनांक 18 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु रु० 25,000-00 मात्र (रु० पचीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फांट अपने स्तर से किया जाय।
- उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय।
- इसे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा।
- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।
- उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-बी०एम०-13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- पुनर्विनियोग के पश्चात् यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में वर्ष भर की आवश्यकता के सापेक्ष धनराशि कम न हो।
- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)-00- की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन "क" के स्तम्भ-1 के लेखाशीर्षक के परिचयों से पुनर्विनियोग से वकन किया जाएगा जो साथ में संलग्न है।

कमश.....2 पर

राष्ट्रीय गणना-विज्ञान केन्द्र

देहरादून

हाथी न० 809 दिनांक 14-4-08

MW

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 340एन.पी./XXVII-4/2007, दिनांक 07मार्च 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।  
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,  
/ (आर0पी0 फुलोरिया)  
संयुक्त सचिव ।

संख्या 2074 /XII/08/82(26)/2003 तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
- 5 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 6 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून ।
- 7 वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन ।
- 8 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,  
/ (आर0पी0 फुलोरिया)  
संयुक्त सचिव ।

आय - व्ययक प्रपत्र-१५

विभाग का नाम :- पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण अभिव्यवस्था सेवा अनुभाग

अनुदान संख्या-१९

पुनर्विनियोग २००७-२००८ / आयोजनेत्तर पक्ष  
(घनराशि हजार रुपये में)

वजेट प्राप्तिमान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक विवरण	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (संरक्षण) घनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें घनराशि को स्थानान्तरित किया जाता है	पुनर्विनियोग क बाद स्तम्भ-५ की कुल घनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-१ में अवशेष घनराशि	औचित्य
१	२	३	४	५	६	७	८
२५१५-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-००-आयोजनेत्तर-८००-अन्य व्यय -०७- राज्य निर्वाचन आयोग(जिला स्तरीय)				२५१५-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-००-८००-अन्य व्यय-०७- राज्य निर्वाचन आयोग(जिला स्तरीय)			क- वचत विभाग की वास्तविक आवश्यकतानुसार इस मद में उपलब्ध है। ख-मानक मदों में संगत लेखों में वजेट व्यवस्था कम होने के कारण
२७- चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय-५०	-	२५	२५	०१-वेतन ०६- अन्य भत्ते ४८-महंगाई वेतन	१७ ०५ ०३	-	
योग:-	५०	२५	२५	२५	१६२	-	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग में वजेट में अनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं नियमों का उल्लेख नहीं होता है।

( आर०पी० फुलोरीया )  
संयुक्त सचिव.

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त विभाग  
संख्या / वि०अनु०-४ / २००८

सेवा में  
महालेखाकार,  
उत्तराखण्डमाजरा, सहरनपुररोड, देहरादून

पुनर्विनियोग स्वीकृत  
(अर्जुन सिंह)  
अपर सचिव.

(आर०पी० फुलोरीया)  
संयुक्त सचिव

संख्या ७८५ / XII / ०८ / ८२(२६) / २००३ दिनांक १७ फरवरी २००८  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. सचिव, वित्त, कर्मचारी / कर्मचारी विभाग, उत्तराखण्ड।
३. वित्त अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन।
४. माई फाइल।